आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 07.04.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने तेल कंपनियों को घरेलू गैस सिलेंडरों का बैकलॉग तत्काल समाप्त करने और चारधाम यात्रा के दौरान व्यावसायिक गैस की आपूर्ति निर्बाध रखने के निदेश दिए।
- आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाने के निर्देश दिए; आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर दिया जोर।
- राज्य सरकार साढ़े तीन करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से 21 प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का कायाकल्प करेगी।
- ऋषिकेश में गंगा बैराज पर सी–प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग की गई।

गैस आपूर्ति

चारधाम यात्रा से पहले राज्य में गैस आपूर्ति को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने देहरादून में संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने तेल कंपनियों को निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलेंडरों का बैकलॉग तत्काल समाप्त किया जाए और यात्रा के दौरान व्यावसायिक गैस की आपूर्ति निर्बाध रखी जाए, ताकि होटल, ढाबा और पर्यटन से जुड़े प्रतिष्ठानों को कोई परेशानी न हो।

मुख्य सचिव ने कहा कि गैस की उपलब्धता बढ़ाकर बाजार में अनावश्यक दबाव और पैनिक की स्थिति से बचा जाए। जिलाधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्रों में गैस आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखने और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में गैस आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है और पैनिक बुकिंग में कमी आई है।

वहीं, गैस के दुरुपयोग पर कार्रवाई के तहत राज्यभर में अभियान जारी है। अब तक हजारों निरीक्षण किए जा चुके हैं और कई सिलेंडर जब्त करने के साथ एफआईआर और गिरफ्तारियां भी हुई हैं।

निर्देश

आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कपाट खुलने से पहले यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा मिल सके।

जिलाधिकारी ने बताया कि बारिश और कमर्शियल गैस आपूर्ति की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है और समय से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

उन्होंने संबंधित एजेंसियों को यात्रा मार्गों के सुधारीकरण, मलबा हटाने और वैकल्पिक मार्गों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने को कहा गया।

गैस आपूर्ति को लेकर पूर्ति विभाग को पारदर्शी वितरण और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सफाई व्यवस्था को मजबूत करने, कूड़ा प्रबंधन पर ध्यान देने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा गया।

<u>निर्देश</u>

देहरादून में विवाह समारोह के लिए गैस सिलेंडर प्राप्त करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब शादी के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही दिए जाएंगे और इसके लिए 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट–

जिलाधिकारी सविन बंसल ने निर्देश दिए हैं कि आवेदक को विवाह कार्ड, आधार कार्ड और शपथ पत्र के साथ आवेदन करना होगा। यह आवेदन विवाह तिथि से 10 से 12 दिन पहले संबंधित कार्यालय में करना अनिवार्य किया गया है।

प्रशासन के अनुसार सिलेंडर अस्थायी रूप से दिए जाएंगे और उपयोग के बाद उन्हें वापस करना होगा। इसके लिए गैस एजेंसियों को अपने स्टॉक का एक हिस्सा सुरक्षित रखने को कहा गया है।

एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और अनियमित उपयोग पर सिलेंडर जब्त किए जा रहे हैं। साथ ही छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

प्रशासन ने बताया कि गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है और पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है।

<u>आपदा प्रबंधन</u>

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के उपयोग से उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मॉडल राज्य बनाया जाए।

श्री कौशिक ने आपदा से पहले, आपदा के दौरान और बाद की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिला स्तर पर व्यवस्थाएं मजबूत करने और संचार प्रणाली को बेहतर बनाने पर जोर दिया, ताकि सूचनाओं का त्वरित आदान–प्रदान हो सके।

उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम स्तर तक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर 'आपदा मित्र' और 'आपदा सखी' तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण देने और प्रोत्साहन देने की बात कही।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री ने संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने, भूस्खलन संभावित स्थानों के उपचार को प्राथमिकता देने और पूर्वानुमान व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी दिए।

आश्वासन

केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आश्वासन दिया है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में अंतर–मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि सरकार वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति पर नजर रख रही है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की संयुक्त सचिव सी शिखा ने कहा कि देश में गेहूं और चावल का पर्याप्त बफर स्टॉक है।

धनराशि स्वीकृति

उत्तराखंड सरकार ने जर्जर विद्यालय भवनों के सुधार के लिए 21 प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प का निर्णय लिया है। इसके लिए 3 करोड़ 52 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

शिक्षा विभाग के अनुसार चयनित विद्यालयों में भवनों का पुनर्निर्माण, छत, फर्श और चारदीवारी सहित मरम्मत कार्य किए जाएंगे। निर्माण कार्य के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी दी गई है।

यह योजना पिथौरागढ़, देहरादून, ऊधमसिंह नगर और अल्मोड़ा जिलों में लागू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य जर्जर विद्यालयों को सुधारकर छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इन कार्यों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

सफल ट्रायल लैंडिंग

ऋषिकेश में गंगा बैराज पर सी–प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग की गई है, जिसे राज्य में हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार का मानना है कि सी–प्लेन सेवा शुरू होने से चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे पर्यटक कम समय में ऋषिकेश और आसपास के प्रमुख स्थलों तक पहुंच सकेंगे।

योजना के तहत भविष्य में इस सेवा को टिहरी झील, नैनीताल झील और अन्य जलाशयों तक भी विस्तार देने की तैयारी है, जिससे राज्य में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

सख्ती

केदारनाथ यात्रा से पहले हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर होने वाली साइबर ठगी पर रुद्रप्रयाग पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर के निर्देश पर जिले में साइबर फ्रॉड कम्बैट फोर्स का गठन किया गया है, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर नज़र रखी जा रही है। एक रिपोर्ट–

इस अभियान के तहत सोशल मीडिया पर कार्रवाई करते हुए 111 में से 106 फर्जी फेसबुक पेज हटाए गए हैं, जबकि 16 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी संदिग्ध गतिविधियों के चलते रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे कई मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया गया है और अन्य नंबरों पर कार्रवाई जारी है।

पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों और वेबसाइट्स पर भी निगरानी बढ़ाई है और कई मामलों में कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे हेलीकॉप्टर टिकट केवल अधिकृत वेबसाइट से ही बुक करें और किसी भी फर्जी लिंक, सोशल मीडिया विज्ञापन या व्हाट्सएप संदेश के झांसे में न आएं। साथ ही किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने को कहा गया है।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर..

पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है– भय, भ्रष्टाचार व अपराध की सरकार उखाड़ फेंकेगी बंगाल की जनता, लोगों ने बनाया परिवर्तन का मन।

पौड़ी जिला अस्पताल में करोड़ों की सीटी स्कैन मशीन खराब, प्रमुख अधीक्षक निलंबित– अमर उजाला का शीर्षक– खबर के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दिए कार्रवाई के निर्देश।

प्रदेश के 14 लाख कार्डधारकों को मिलेगा तीन माह का राशन– दैनिक जागरण इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है– वर्षा और आपदा को ध्यान में रखते हुए अप्रैल, मई और जून का राशन मिलेगा एक साथ।

भूमि से जुड़े विवादों में पुलिस अब सीधे मुकदमा दर्ज नहीं करेगी– हिन्दुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है– गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा लैंड फ्रॉड समन्वय समिति पहले करेगी शिकायतों की जांच, फिर होगी आगे की कार्रवाई।

और दून पुलिस के नाइट स्ट्राइक की खबर पर नवोदय टाइम्स लिखता है– पब, बार, होटल, रेस्टोरेंट में औचक छापेमारी में 10 गिरफ्तार, नियमों के उल्लंघन में हुई कार्रवाई।